'आर्थिक समृद्धि भारत की महत्त्वाकांक्षा और नियति दोनों'

आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा कि भारत तेज आर्थिक वृद्धि और व्यापक आर्थिक स्थिरता के चरण में प्रवेश कर चुका है

सुब्रत पांडा
मुंबई, 11 मई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा कि अब यह बहस का विषय नहीं रह गया कि भारत समृद्ध होगा या नहीं बल्कि अहम सवाल यह है कि आर्थिक संपन्नता कितनी तेजी से, कितने व्यापक स्तर पर और कितनी बराबरी के साथ राज्यों और उनकी जनता के बीच साझा की जाएगी। डिप्टी गवर्नर गुप्ता ने सोमवार को कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि भारत में तीव्र विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता का एक सकारात्मक दौर शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा, 'आर्थिक समृद्धि ही भारत की महत्त्वाकांक्षा और नियति है।' उन्होंने यह भी कहा कि अगर पिछले दो दशकों की आर्थिक गति इसी तरह जारी रही तो वर्ष 2046-47 तक औसत राज्य प्रति व्यक्ति आय उच्च आय सीमा के करीब पहुंच सकती है।

गुप्ता ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1980 के दशक में औसतन 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 1990 के दशक में 5.8 प्रतिशत हो गई और फिर 2000 के दशक में बढ़कर 6.3 प्रतिशत, 2010 के दशक में 6.6 प्रतिशत और हाल के चार वर्षों में 7.7 प्रतिशत तक पहुंच गई। प्रति व्यक्ति आय में यह तेजी और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिख रही है। वर्ष 1981 में यह लगभग 274 अमेरिकी डॉलर और 1991 में 306 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में लगभग 2700 अमेरिकी डॉलर हो गई है।

उन्होंने कहा, 'हालांकि, प्रति व्यक्ति आय शुरू में दोगुना होने में दो दशकों से अधिक का समय लग गया मगर बाद के दो दशकों में यह लगभग पांच गुना बढ़ गई है। यह आर्थिक विकास की गति में एक स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है।' उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि में कमी भी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी में योगदान दिया है।

उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि, जो कभी वैश्विक औसत से काफी अधिक थी, में लगातार कमी आई है और लगभग 2014 से यह वैश्विक स्तर के करीब पहुंच गई है जिससे प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की प्रति व्यक्ति आय 2025 में बढ़कर 2,818 डॉलर, 2026 में 3,051 डॉलर और 2030 में 4,346 डॉलर होने का अनुमान जताया है। गुप्ता ने कहा कि भारत की बेहतर होती व्यापक आर्थिक स्थिरता मुद्रास्फीति, चालू खाता संतुलन, राजकोषीय स्थिति, ऋण गुणवत्ता और वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में टिकाऊ और मजबूत परिणामों में परिलक्षित होती है। उन्होंने इसका श्रेय राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन ढांचा, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और 2016 में शुरू की गई मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण व्यवस्था जैसे सुधारों को दिया।

डिप्टी गवर्नर ने कहा कि राज्यों की आर्थिक तरक्की भी खूब हुई है पिछले दो दशकों में प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में राज्यों की औसत प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में लगभग पांच गुना और स्थिर रुपये में तीन गुना से अधिक बढ़ी है जो भारत की दीर्घकालिक आय वृद्धि की मजबूती और निरंतर गति को रेखांकित करती है।

उन्होंने कहा, 'हालांकि, आय वृद्धि की रफ्तार देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग रही है। कुछ राज्य पिछले दो दशकों में पांच से दस गुना अधिक समृद्ध हुए हैं जबकि अन्य राज्यों में लगभग तीन गुना की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है।' उन्होंने यह भी कहा कि अधिक समृद्ध राज्यों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर अपेक्षाकृत कम समृद्ध राज्यों की तुलना में तेजी से बढ़ा है मगर हाल के वर्षों में अमीर और गरीब राज्यों के बीच विकास का अंतर कम हुआ है।

गुप्ता ने कहा, 'कुल मिलाकर पूर्व में संपन्न राज्यों का बेहतर प्रदर्शन न केवल उच्च आय वृद्धि बल्कि धीमी जनसंख्या वृद्धि के कारण भी रहा है। औसत आय स्तर से ऊपर के राज्यों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर अधिक है और जनसंख्या वृद्धि दर धीमी है जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हो रही है।'

हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि हाल के वर्षों (वर्ष 2011-12 से वर्ष 2023-24) में उन राज्यों में उपभोग तेजी से बढ़ रहा है जहां पहले यह कम रहा था। यह भारत के राज्यों में जीवन स्तर के वितरण में समानता की ओर एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।

उन्होंने कहा, 'अगर आर्थिक वृद्धि की रफ्तार यूं ही कायम रही तो कई राज्य 2047 तक (समृद्धि के प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार) 'अमीर' बन जाएंगे या अमीर बनने के करीब पहुंच जाएंगे।'

गुप्ता के मुताबिक वर्ष 2047 तक पूर्ण आर्थिक संपन्नता हासिल करने के लिए मौजूदा आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखने या उसे और तेज करने के लिए राज्यों के स्तर पर हमारे विकास ढांचों का विस्तार करना जरूरी होगा।

तेल के झटके से बढ़ सकता है चालू खाते का घाटा : अर्थशास्त्री

हिमांशी भारद्वाज और अंजलि कुमारी
नई दिल्ली/ मुंबई, 11 मई

भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) वित्त वर्ष 2026-27 में उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकता है क्योंकि पश्चिम एशिया संघर्ष से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, धन प्रेषण पर दबाव पड़ रहा है और निर्यात वृद्धि कमजोर हो रही है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बड़ा जोखिम पूंजी खाते की ओर भी हो सकता है। सीएडी के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.5 प्रतिशत से लेकर 2.4 प्रतिशत तक रहने के अनुमान लगाया जा रहा है।

क्रिसिल ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026 में सीएडी के जीडीपी के 0.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 में 2.2 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही, उसने ब्रेंट क्रूड का पूर्वानुमान पहले के 82-87 डॉलर प्रति बैरल से संशोधित कर 90-95 डॉलर प्रति बैरल कर दिया है। क्रिसिल ने चेतावनी दी कि तेल, गैस और उर्वरक की ऊंची कीमतें आयात बिल पर और अधिक दबाव डालेंगी। क्रिसिल की भारत संबंधी नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में लंबे समय तक चले संघर्ष और इसके कारण तेल व गैस उत्पादन तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में आई बाधा से क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी। परिणामस्वरूप, भारत को पश्चिम एशिया से आने वाले प्रेषण पर भी असर पड़ सकता है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने मई की शुरुआत में कहा था कि यह संघर्ष भारत के लिए बहु-आयामी वृहद आर्थिक चुनौती पैदा करता है जिससे चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 26 में 1 प्रतिशत से कम से बढ़कर वित्त वर्ष 27 में जीडीपी के 2 प्रतिशत से अधिक तक जा सकता है।

फिलहाल, अर्थशास्त्रियों का व्यापक मत है कि वित्त वर्ष 27 बाहरी खाते के लिए वित्त वर्ष 26 की तुलना में कठिन वर्ष साबित हो रहा है। उनके मुताबिक सीएडी का सटीक आंकड़ा कच्चे तेल की कीमतों की दिशा और पश्चिम एशिया संघर्ष की अवधि पर निर्भर करेगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि वित्त वर्ष 27 में चालू खाता घाटा 1.5-2 प्रतिशत के दायरे में रह सकता है। इसका कारण व्यापक व्यापार घाटा और खाड़ी देशों से कम प्रेषण होगा। उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन हमें आईटी जैसी सेवाओं के निर्यातकों से कुछ सहारा मिल रहा है।'

सबनवीस ने कहा कि अल्पावधि में भारत ऐसे बाहरी प्रवाहों को संतुलित करने के लिए बहुत काम कर सकता है और असली दबाव पूंजी खाते पर है न कि केवल चालू खाते पर। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इस तरह के माहौल में एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों) को वापस लाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है।'

इसी तरह बेस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रनील पाल ने कहा कि मौजूदा बहस चालू खाता घाटे पर बहुत अधिक केंद्रित है, जबकि असली जोखिम पूंजी खाते में है। उन्होंने कहा, 'आज की बड़ी चिंता यह है कि भारत को पर्याप्त सकल एफडीआई प्रवाह मिलते रहने के बावजूद, शुद्ध प्रवाह बेहद कमजोर हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर पुनर्प्रेषण हो रहा है।' उन्होंने जोड़ा कि नीति प्रतिक्रियाएं चालू खाते के दबाव को खपत पर अंकुश लगाकर कम करने की बजाय पूंजी प्रवाह सुधारने पर केंद्रित होनी चाहिए।

एमके ग्लोबल फाइनैंशियल सर्विसेज ने अपेक्षाकृत हल्का लेकिन चिंताजनक अनुमान दिया है, जिसमें वित्त वर्ष 27 में सीएडी/जीडीपी को 1.7 प्रतिशत पर रखा गया है, जब ब्रेंट का औसत मूल्य 80 डॉलर प्रति बैरल माना गया है। पहले यह 1.3 प्रतिशत था जब ब्रेंट 70 डॉलर पर अनुमानित था। कंपनी ने कहा कि ब्रेंट में हर 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि घाटे को 0.45 प्रतिशत अंक तक बढ़ा सकती है।

केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री माधवन जी. कुट्टी ने कहा, 'कच्चे तेल पर प्रतिकूल झटका, जो वृद्धविराम होने पर भी 100 से 110 डॉलर के बीच रह सकता है, और माल निर्यात में 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 27 में 1.8 से 1.9 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार की टिप्पणी ने बहस में एक नया पहलू जोड़ दिया जब उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता के बीच राष्ट्रीय हित में परिवारों से एक वर्ष तक गैर-जरूरी सोने की खरीद टालने का आग्रह किया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया, क्योंकि बढ़ते बुलियन आयात भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार संतुलन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। थिंक टैंक ने सरकार से भारत-यूएई व्यापार समझौते के तहत कीमती धातुओं पर दी गई शुल्क रियायतों की समीक्षा करने का आग्रह किया। उसने कहा कि भारत का सोना आयात 2022 में 36.5 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 58.9 अरब डॉलर हो गया। इसके परिणामस्वरूप, थिंक टैंक ने भारत के व्यापार संतुलन की रक्षा के लिए सख्त मूल नियमों और भविष्य के व्यापार समझौतों से कीमती धातुओं को बाहर करने की सिफारिश की है।

इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि बेसलाइन परिदृश्य में, जहां कच्चा तेल औसतन 85 डॉलर प्रति बैरल है, सीएडी वित्त वर्ष 27 में जीडीपी का 1.7 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, 'जब कीमतें अधिक हों तो ईंधन की मांग को नियंत्रित करने के उपाय निश्चित रूप से सीएडी में वृद्धि को रोकने में मदद करेंगे। अल-नीनो के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में सोने की मांग इस वर्ष वैसे भी कमजोर रह सकती है।'

अप्रैल में जीवन बीमा के एनबीपी में सालाना 39 फीसदी की तेजी

आतिरा वारियर
मुंबई, 11 मई

अप्रैल में जीवन बीमा कंपनियों की बेची गई नई पॉलिसी का प्रीमियम (एनबीपी) 39 प्रतिशत बढ़कर 30,550.38 करोड़ रुपये रहा था जो पिछले साल की समान अवधि में 21,964.2 करोड़ रुपये था। यह वृद्धि सरकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और निजी जीवन बीमा कंपनियों दोनों के मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई।

विश्लेषकों के अनुसार, इस वृद्धि का समर्थन न केवल आधार के कम होने से हुआ बल्कि खुदरा जीवन बीमा पॉलिसी पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी के बाद जारी रफ्तार से भी मिला। जीवन बीमा परिषद के डेटा के अनुसार, एलआईसी का एनबीपी 38 प्रतिशत बढ़कर 18,782 करोड़ रुपये हो गया जबकि निजी जीवन बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय 40.88 प्रतिशत बढ़कर 11,768 करोड़ रुपये पहुंच गई।

निजी कारोबार के तहत एनबीपी 19.35 प्रतिशत बढ़कर 9,458.5 करोड़ रुपये हो गया जबकि समूह कारोबार में सालाना 50.23 प्रतिशत की तेजी आई और यह 21,091.88 करोड़ रुपये हो गई।

नुवामा के विश्लेषक का कहना है, 'टर्म इंश्योरेंस में जीएसटी के कारण उद्योग को मजबूती मिली है। ऐसा लगता है कि इस रफ्तार का कुछ हिस्सा अप्रैल में भी बना रहा, जिससे मार्जिन में लाभ के संकेत मिले।'

निजी बीमाकर्ताओं में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने सालाना एनबीपी में 79.6 फीसदी की तेजी दर्ज की और यह बढ़कर 3,040.96 करोड़ रुपये हो गया। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने 30.27 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की और यह 2,531.42 करोड़ रुपये हो गया जबकि आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 25.61 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की और यह 1,296.4 करोड़ रुपये हो गया।

वहीं बजाज लाइफ इंश्योरेंस की नई बेची गई पॉलिसी का प्रीमियम सालाना 30.25 फीसदी बढ़कर 936.99 करोड़ रुपये हो गया जबकि ऐक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 17.58 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की और यह 696.2 करोड़ रुपये हो गया।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"). NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES (AS DEFINED IN THE DRHP) IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SEBI ICDR REGULATIONS

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR code to view the DRHP)

GAURIK GROUP

GAURIK FASHIONS LIMITED

Our Company was originally incorporated as a private limited company under Companies Act, 2013 in the name and style of "Gaurik Fashions Private Limited" vide Certificate of Incorporation dated March 24, 2017, issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre, bearing CIN U52609DL2017PTC315030. Further, our company converted from private limited to a public limited company pursuant to a special resolution passed by the members of our Company at the Extra-Ordinary General Meeting held on November 28, 2024 and name of our Company changed from "Gaurik Fashions Private Limited" to "Gaurik Fashions Limited" and Central Processing Centre, has issued a new certificate of incorporation consequent upon conversion dated December 23, 2024, bearing CIN U52609DL2017PLC315030. Further, pursuant to change in the object clause of the company, the Central Processing Centre has issued a new certificate of incorporation dated November 26, 2025, bearing CIN U46909DL2017PLC315030. For further details, see *"History and Certain Corporate Matters – Brief History of our Company"* on page 189 of the draft red herring prospectus dated May 10, 2026 (the "**DRHP**" or the "**Draft Red Herring Prospectus**").

Corporate Identity Number: U46909DL2017PLC315030
Registered Office: 1st Floor, Rear Portion, Block A, Centre for Indian Classical dance (CICD), Gulmohar Park, Hauz Khas, New Delhi, 110016, India.
Corporate Office: 1867, Hennur 4th & 5th Floor, 5th Block, 1st Stage, HBR Layout, Bengaluru- 560043, Karnataka, India. **Contact Person:** Yogita, Company Secretary and Compliance Officer
Tel: 011-40113227, **E-mail:** cs@gaurikgroup.com, **Website:** www.gaurikgroup.com

OUR PROMOTERS: VISHNU PILLAI, RAJESH DUDI, SWATI SINHA, AND ISHA DUDI

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 70,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF GAURIK FASHIONS LIMITED ("COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 62,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY OUR COMPANY ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 8,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION ("OFFERED SHARES") BY ARIES OPPORTUNITIES FUND LIMITED (THE "INVESTOR SELLING SHAREHOLDER"), AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDER ("OFFER FOR SALE", AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER"). THE OFFER WILL CONSTITUTE [●]% OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT, AS MAY BE PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, TO ANY PERSON(S), AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20.00% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE. PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT INTO LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE OFFER PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN [●] EDITIONS OF [●], (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), [●] EDITIONS OF [●], (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF DELHI WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES, IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company, in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a public notice and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the members of the Syndicate, the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**"), and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank(s), as applicable.

This Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process and is in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein in terms of Regulation 32(1) of the SEBI ICDR Regulations, not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**", and such portion, the "**QIB Portion**") provided that our Company, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which (i) 33.33% shall be reserved for domestic mutual funds; and (ii) 6.67% shall be reserved for life insurance companies and pension funds, subject to valid Bids being received from domestic mutual funds, life insurance companies and pension funds at or above the Anchor investor Allocation Price. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹0.20 million and up to ₹1.00 million; and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹1.00 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("**RIBs**") in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Retail Portion**"), subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further all potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective bank accounts (including UPI ID for UPI Bidders using UPI Mechanism) (as defined hereinafter) in which the Bid amount will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank(s), as applicable, to participate in the Offer. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion of the Offer through the ASBA process. For details, see *"Offer Procedure"* on page 304 of the DRHP.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offer of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP dated May 10, 2026 with SEBI and the Stock Exchanges on May 10, 2026.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from the date of publication of this public announcement by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com where the Equity Shares are proposed to be listed, the website of the BRLMs, i.e. Credora Partners Private Limited at www.credorapartners.com and Unistone Capital Private Limited at www.unistonecapital.com and the website of our Company at www.gaurikgroup.com. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of public are requested to send a copy of their comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein below. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the BRLMs and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Offer on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of publication of this public announcement in accordance with Regulation 26(2) of SEBI ICDR Regulations.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* on page 29 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("**Red Herring Prospectus**") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus, as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP.

The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the main board of the Stock Exchanges.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 189 of the DRHP.

The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital, capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see *"Capital Structure"* on page 84 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
CREDORA PARTNERS	UNISTONE	MASS
Credora Partners Private Limited 6th Floor, B Wing, GSC Tower, Sector 30, Gurugram – 122001, Haryana, India **Telephone:** +91-124-4293471 **Email:** info@credorapartners.com **Contact Person:** Pankaj Kumar Pasi **Website:** www.credorapartners.com **Investor Grievance ID:** investors@credorapartners.com **SEBI Registration Number:** INM000013411	**Unistone Capital Private Limited** A/305, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4604 6494 **Email:** mb@unistonecapital.com **Contact Person:** Deep Shah **Website:** www.unistonecapital.com **Investor Grievance ID:** compliance@unistonecapital.com **SEBI Registration Number:** INM000012449	**Mas Services Limited** T-34 Floor, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II New Delhi- 110020 **Telephone Number:** 011-26387281-83, 011-41320335 **Fax:** 011-26387384 **Email:** info@masserv.com and investor@masserv.com **Contact Person:** N.C. Pal **Website:** www.masserv.com **SEBI Registration Number:** INR000000049

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Yogita
1st Floor, Rear Portion Block A Centre for Indian Classical dance (CICD), Gulmohar Park Hauz Khas, New Delhi, 110016 India.
Telephone: 011-40113227, **E-mail:** cs@gaurikgroup.com, **Website:** www.gaurikgroup.com

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **GAURIK FASHIONS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Yogita
Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: May 11, 2026

GAURIK FASHIONS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated May 10, 2026 with SEBI and the Stock Exchanges on May 10, 2026. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, on the websites of the BRLMs, i.e., Credora Partners Private Limited at www.credorapartners.com and Unistone Capital Private Limited at www.unistonecapital.com and on the website of our Company at www.gaurikgroup.com**.** Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see the section titled *"Risk Factors"* on page 29 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision.

This announcement does not constitute an offer of the Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and the Equity Shares may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933 or an exemption from registration. Any public offering of the Equity Shares to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the Equity Shares are not being offered or sold in the United States.

KIRIN